पायदार तिजारत का मुआहिदा अफ़गानिस्तान से किया है; अगर हां, तो वह क्या है।

श्री दिनेश सिंह : जी नहीं। और कोई वायदा नहीं किया है।

SHRI SHRI CHAND GOYAL: India has very close trade relations with Pakistan and in fact most of the consumer goods in Afghanistan are exported from India to Afghanistan. May I know whether Government has got any survey conducted to find out as to in what fields and for what Indian goods there is a market in Afghanistan so that we can increase our exports to Afghanistan and that of Afghan goods to India?

SHRI DINESH SINGH: The hon. Member mentioned that we had very close relations. I would like to say that we have still better relations than what we had in the past.

SHRI PILOO MODY: After your visit?

SHRI BAL RAJ MADHOK: We want them to be still better.

SHRI DINESH SINGH: I do not know about my visit. There have been some romantic speculations beyond what.... *(Interruption)*

SHRI J. B. KRIPALANI: Did this romance take place in Afghanistan or beyond Afghanistan?

SHRI DINESH SINGH: Leaving out the element of speculation in the whole question, what I had said is substantiated by facts and figures. Our trade with Afghanistan ten years ago was of the order of Rs. 3.35 crores and last year it went up to Rs. 7.50 crores. It is certainly an increase by any standard. So far as the question of making a study of the Afghan market is concerned, this is being done by the traders there and by our mission. There is a long list attached to the agreement about the goods which can be sold from India to Afghanistan.

SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH: You are well aware, Sir, of recent press reports about our efforts to undertake commercial sales of small arms and army equipment to Malaysia and South East Asian countries. Has the hon. Commerce Minister had any talks about commercial sales of small arms and defence equipment to Afghanistan?

SHRI DINESH SINGH: No, Sir.

श्री महाराज सिंह भारती : जैसा कि मंत्री जी ने बताया है, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध चाहे कितने ही मधुर और रोमान्टिक क्यों न हों, लेकिन, बीच में जो पाकिस्तान पड़ा हुआ है, वह न तो अफ़गानिस्तान से रोमांस करना चाहता है और न हम से और वही लैंड रूट है। अगर लैंड-रूट खुल भी जाये, तो इस बात की कोई गारण्टी नहीं है कि आता हुआ माल किसी दिन ज़ब्त नहीं कर लिया जायेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत यूरोप से ले कर मलेशिया तक अन्तर्राष्ट्रीय रोड़वेज की एक योजना बनाई गई है। वह सड़क अफ़गानिस्तान और हिन्दुस्तान में से हो कर गुजरती है। क्या सरकार ने कभी इस बात का प्रयास किया है कि ऐसी व्यवस्था की जाये कि उस सड़क से दो देशों के माल के गुजरने पर कोई पाबन्दी नहीं लगाई जायेगी, सिवाये कस्टम वगैरह के कायदों के और संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात की गारण्टी करे?

श्री दिनेश सिंह : जी हां। प्रयास जरूर किया है। माननीय सदस्य जिस सड़क की बात कह रहे हैं—एशियन हाई-वे की, जिस के बारे में एकाफ़े में बात चीत हो रही है, उस के पीछे भी यही विचार है कि उस के ज़रिये खुली तिजारत हो सके और उस में कोई रोक-टोक न हो, अलावा उन नियमों के, जो हर एक अपने यहां बना सकता है।

BLACK-LISTING OF MESSRS. AMINCHAND PYARELAL

*694. SHRI ABDUL GHANI DAR: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the firm of M/s. Aminchand Pyarelal was black-listed during 1963-64;

(b) if so, for what period, how many times and on what grounds;

(c) the grounds on which the order of black-listing the said firm was withdrawn; and

(d) whether any Chief Minister sent a D.O. letter to the Union Government in their favour and, if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL MINES AND METALS (SHRI RAM SEWAK): (a) to (c). During 1963-64, the firm of Messrs. Amin Chand Pyarelal was not black-listed by the Department of Iron & Steel. However, an order under the Standardised Code, banning them and their associates for a period of two years was issued by the Iron and Steel Controller on 31st July, 1963. The ground for banning the firm and their associates was the failure on the part of M/s. Surrendra Overseas (Private) Limited, an associate of Messrs. Amin Chand Pyarelal, to account for 724 tonnes of Steel Rounds of substandard quality, imported by them in 1957. The ban order was not withdrawn during, but was allowed to expire at the end of, the currency of the two-year period, *viz.*, on 31st July, 1965.

(d) According to information available, no letter was addressed by any Chief Minister to the Union Government regarding the ban order of 31st July, 1963, against M/s. Amin Chand Pyarelal.

श्री अब्दुल गनी दार : क्या वजीर साहब बताएंगे कि अमी चंद प्यारे लाल को एक बार नहीं दो बार ब्लैक लिस्ट पर किया गया और दो बार फिर उन को व्हाइट लिस्ट पर लाया गया? अक्तूबर में उन को ब्लैक लिस्ट पर किया गया और जनवरी में व्हाइट लिस्ट पर लाया गया। तो इन दो महीनों में सरकार को क्या उन पर यकीन हो गया कि जिस की वजह से उन को ब्लैक लिस्ट से व्हाइट लिस्ट पर किया गया?

दूसरे, क्या यह सच है कि इस सिलसिले में पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री प्रताप सिंह कैरों ने अपना डी० ओ० लखा था जो डी० ओ० कि "हिस्टारिक एन्क्वायरी आफ्टर वारेन हेस्टिंग्ज़" में छप भी गया था और जिस का ज़िक्र राज्य सभा में बार-बार चलता रहा और सरकार ने माना कि उन्होंने डी० ओ० लिखा तो क्या उन के डी० ओ० की वजह से उन को ब्लैक लिस्ट से व्हाइट लिस्ट पर किया गया?

[کیا وزیر صاحب بتائیں گے کہ امی چند پیارے لال کو ایک بار نہیں دو بار بلیک لسٹ پر کیا گیا اور دو بار کر پھر ان کو وھائٹ لسٹ پر لایا گیا : اکتوبر میں ان کو بلیک لسٹ پر کیا گیا اور جنوری میں وھائٹ لسٹ پر لایا گیا - تو ان دو مہینوں میں سرکار کو کیا ان پر یقین ہو گیا کہ جس کی وجہ سے ان کو بلیک لسٹ سے وھائٹ لسٹ پر کیا گیا -

دوسرے کیا یہ سچ ہے کہ اس سلسلے میں پنجاب کے بہوت پورو مکھیہ منتری شری پرتاپ سنگھ کیروں نے اپنا پتی - او لکھا تھا جو پتی - او - کہ ہسٹورک انکوائری افٹر وارن ہسٹنگز میں چھپ بھی گیا تھا اور جس کا ذکر راجیہ سبھا میں بار بار چلتا رہا اور سرکار نے مانا کہ انہوں نے پتی - او - لکھ تو کیا ان کے پتی - او - کی وجہ سے ان کو بلیک لسٹ سے وھائٹ لسٹ پر کیا گیا-

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री प्र० चं० सेठी) : अध्य होदय, जैसा कि उत्तर में कहा गया है इस फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया। लेकिन इनके साथ बिजनेस सस्पेंड करने का आदेश 1962 में दिया गया जो अभी तक कार्यान्वित है। इस के बाद 1963–64 में इन का बिजनेस बैन किया गया। वह आर्डर 1965 में एक्सपायर हो गया। इस के पश्चात् 1966 में फिर पी० ए० सी० की रिपोर्ट के बाद इनका बिजनेस 3 साल के लिए बैन किया गया। वह आज भी कार्यान्वित है। जहां तक ब्लैक लिस्ट का ताल्लुक है फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया। जहां तक पंजाब के भूत-पूव मुख्य मंत्री श्री प्रताप सिंह कैरो का ताल्लुक है, उन्होंने इन की ब्लैक लिस्टिंग के सम्बन्ध में कोई पत्र नहीं लिखा। हां, इंडस्ट्रिअल लाइसेंसिंग के सम्बन्ध में उन के कुछ पत्र थे।

श्री अब्दुल गनी दार : क्या वजीर साहब बताएंगे कि इन का, बदकिश्मती से दो मिनिस्टर साहबान के साथ ताल्लुक रहा : एक दफा सरदार स्वर्ण सिंह ने उन को ब्लैक लिस्ट पर किया और एक दफा श्री मनु भाई शाह ने इन को ब्लैक लिस्ट पर किया। ब्लैक लिस्ट होने के बाद इन्होंने तरह-तरह की और फर्मों के नाम से, सुरेन्द्र ओवरसीज़ एजेन्सी का तो आप ने जिक्र किया, लेकिन कई और फर्में बना कर उन के नाम से इम्पोर्ट लाइसंस लेने में यह काफ़ी कामयाब रहे, क्या यह सरकार की नोटिस में है यदि था है तो जब उन को ब्लैक लिस्ट किया गया तो जो फर्म उन्होंने नये नाम से बनाई उन को फिर से इजाजता क्यों दी गई ?

[کیا وزیر صاحب بتائیں گے کہ ان کا بدقسمتی سے دو منسٹر صاحبان کے ساتھ تعلق رہا - ایک دفعہ سردار سورن سنگھ نے ان کو بلیک لسٹ کیا اور ایک دفعہ شری منو بھائی شاہ نے ان کو بلیک لسٹ پر کیا - بلیک لسٹ ہونے کے بعد انہوں نے طرح طرح کی اور فرموں کے نام سے سریندر اوورسیز ایجنسیز کا تو آپ نے ذکر کیا لیکن کئی اور فرمیں بنا کر ان کے نام سے امپورٹ لائسنس لینے میں یہ کافی کامیاب رہے - کیا یہ سرکار کے نوٹس میں ہے - یدی ہے تو جب ان کو بلیک لسٹ کیا گیا تھا تو جو فرمیں انہوں نے نئے نام سے بنائیں ان کو پھر سے اجازت کیوں دی گئی -]

श्री प्र० चं० सेठी : मैं ने तो बताया कि यह ब्लैक नहीं हुए। उन के साथ बिजनेस का सस्पेंसन और बैनिंग हुआ और जो हुआ वह अभी चंद प्यारे लाल ग्रूप के साथ हुआ और वह आर्डर कार्यान्वित रहा।

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं अभी चन्द प्यारे लाल के बारे में सदन में बहुत चर्चा हो चुकी है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं यह ब्लैक लिस्ट करने और उन के साथ बिजनेस पर बैन लगाने, इन दोनों में क्या अन्तर है ? और दूसरे, अभी चंद प्यारे लाल की और से कांग्रेस दल या दूसरे दलों को राजनैतिक चन्दे के

रूप में कितना रुपया दिया गया, इसका ब्योरा मंत्री जी देंगे ?

श्री प्र० चं० सेठी : अध्यक्ष महोदय, ब्लैक लिस्टिंग और बैनिंग या सस्पेंशन आफ बिजनेस का जहां तक ताल्लुक है इस के सम्बन्ध में डाइरेक्टोरेट जनरल आफ सप्लाइ ऐंड डिस्पोजल्स के द्वारा बनाया हुआ एक स्टैंडाइज्ड कोड है, उस के मुताबिक यह कार्यवाही की जाती है। जब किसी फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाता है तो उस के बारे में सारी जानकारी सब मिनिस्ट्रीज़ को सर्कुलेट कर दी जाती है और उस के बाद उन मिनिस्ट्रीज़ के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह भी उस फर्म से कोई ताल्लुक न रखें। जहां तक बैनिंग का ताल्लुक है वह इनफार्मेशन भी सारी मिनिस्ट्रीज को दी जाती है लेकिन उन के लिए आवश्यक नहीं है कि वह अमल तौर पर वैसा करें, वह अपनी इच्छा के अनुसार उस पर कार्यवाही करें या न करें, यह उन के ऊपर छोड़ा जाता है। यह अन्तर दोनों में है। जहां तक राजनैतिक पार्टियों को चन्दा देने का ताल्लुक है मेरे पास उस की जानकारी नहीं है। आम तौर पर सभी पार्टियों को इस तरह का चन्दा लोग देते हैं ?

SHRI S. M. BANERJEE: In this House a question was raised that they wanted an import licence for certain imported articles to complete the Park Hotel in Calcutta. We were assured that this would not be given to them because there were serious charges against this particular firm. But the Hotel has gone up as the Government's promises have gone down. We have seen that in Calcutta. I would like to know whether it is a fact that a bold declaration has been made by one Mr. Jit Paul that since his company and himself have stood 90 per cent of the expenses of Durgapur Congress last year, there is no power on earth which can possibly.... (*Interruptions*)

Mr. SPEAKER: Has he said that he has stood 90 per cent of the expenses of Durgapur Congress?

SHRI S. M. BANERJEE: He has said to many.....

MR. SPEAKER: It is something very strange.... (*Interruptions.*)

SHRI S. M. BANERJEE: My question is this. He has made a statement, when the question was raised by Mr. Limaye and others in this House, that all the Opposition combined together will not be able to beat him because certain Ministers are in his left and right pockets and he has paid a huge amount to Congress coffers....

MR. SPEAKER: He may ask his question.

SHRI S. M. BANERJEE: I want to know why an import licence was given to complete the Hotel, whether there were any restrictions and if so, why those restrictions were not followed, and what was the amount paid to the Congress both for elections and for Durgapur Congress.

SHRI P. C. SETHI: I have no information about this.

SHRI S. M. BANERJEE: No information?

MR. SPEAKER: How can the Steel Ministry have information about Hotels?

Mr. Tiwary.

SHRI D. N. TIWARY: There were serious charges against this firm. May I know whether, at any time in the past, the matter of Aminchand Pyarelal was sent to the Vigilance Commission and their opinion obtained and, if so, what was their opinion?

SHRI P. C. SETHI: The entire deals relating to this firm and others have been gone into by the Sarkar Committee. Their report has come. Their report was also sent to the Vigilance Commission and the Vigilance Commission has concurred with the entire report of the Sarkar Committee.

As far as certain transactions are concerned which relate to contravention of foreign exchange regulations, the matter has been referred by the Sarkar Committee to the Reserve Bank of India and they in their turn have referred the matter to the C.B.I. for inquiry. That inquiry is still going on.

SHRI UMANATH: The latest investigation with regard to the shady deals of this company and its *modus operandi* was by the Sarkar Committee, and that Committee at various places has consistently mentioned that this shady deal was possible because that firm was in a position to get advance information of any intended transactions either by the public sector companies or by the Ministry itself. It has held so in that report. I understand that subsequent to 1961 the Government is in possession of a CBI investigation report about the shady deal of this company which mentions two important dignitaries being the recipients of financial favours from this company, one belonging to the Cabinet level and the other, another very important..... (*Interruptions*)

SHRI S. M. BANERJEE: This is a very serious charge. He should mention the names.

MR. SPEAKER: Not necessary.

SHRI UMANATH: My information is that the CBI investigation report which is in the hands of the Government mentions Mr. Swaran Singh and Mr. Hukam Singh, who is a Governor, as being recipients of financial favours from this company. I am mentioning this because the Sarkar Committee holds that this company has been receiving advance intimation from higher-ups and all those things. My question now is whether the Government placed this CBI investigation report before the Sarkar Committee in order to help it to come to a proper conclusion as to the real culprits behind the entire shady deal. If they had not placed it, I would like to know from the hon. Minister whether the reason was to prevent the committee from catching hold of the real culprits.

SHRI P. C. SETHI: All the relevant papers and records which were asked for by the committee were sent to them.

श्री मधु लिमये : "आस्क्ड फौर नहीं, उन का सवाल दूसरा है। क्या सारे कागतजात खुद आपने रखे"

SHRI P. C. SETHI: I am sorry that the hon. Member is making such remarks about the Ministers and the hon. Governor. No such thing has been said by the Sarkar Committee. On the other hand, the Sarkar Committee has exonerated the two Ministers, Shri Swaran Singh and Shri C. Subramaniam.

SHRI UMANATH: I am referring to the CBI report.

SHRI P. C. SETHI: The Sarkar Committee has not said anything about them. On the contrary, they have said.....

SHRI UMANATH: He is diverting my question. My question was this. Government are in possession of a CBI report. Let him say whether it is true or not. Secondly, I would like to know whether that report was placed before the Sarkar Committee. If it was not placed I would like to know whether the reason was to prevent the real culprits being traced. Let him come out with the CBI report.

SHRI P. C. SETHI: All concerned papers and reports necessary were put before them.

SHRI UMANATH: He is trying to go away from the question. I want a categorical answer in regard to the CBI report.

SHRI P. C. SETHI: I am not trying to go away from the question. Everything which was possible and which was there was placed before them.

SHRI UMANATH: My question has not been answered. I am not asking whether every paper was connected and it was placed. My question is whether the CBI report was placed before them.

MR. SPEAKER: He need not repeat it. The question is very clear. If the hon. Minister has information, let him answer. If he does not have information, let him say that he has no information.

SHRI P. C. SETHI: I do not know to which CBI report the hon. Member is referring. All the connected papers were placed before the committee; they have gone into all the reports, and this matter was referred to the Vigilance Commission, before, and it was

referred to the Commission, even after the inquiry committee's report; so, the Vigilance Commission was in the picture throughout.

SHRI UMANATH: Will he place the CBI report before the House?

MR. SPEAKER: Can the House presume that the CBI report was placed before the Central Vigilance Commission?

SHRI P. C. SETHI: I do not know to which CBI report he is referring. The entire matter was placed before the Vigilance Commission and the inquiry committee and the Vigilance Commission has gone into it, and the Sarkar Committee has gone into it, and the Sarkar Committee's report has also been sent to the Vigilance Commission and the Vigilance Commission has completely concurred with the report.

SHRI INDER J. MALHOTRA: Some time back, the Central Government ordered an inquiry regarding the issue and utilisation of stainless steel quota in Jammu and Kashmir State, and this firm was also involved in it. May I know whether the hon. Minister is aware of this fact that such an inquiry had been ordered, and if so, what has happened to that inquiry?

SHRI P. C. SETHI: I want notice.

श्री शिवनारायण: अभी चन्द प्यारे लाल का बीच में दो वर्ष के लिये सस्पेन्शन था–क्या यह सही है कि उन के जिम्मे सरकार का 195 लाख रुपया इन्कमटैक्स का बाकी था, इस लिये उनको सस्पेंड किया गया था, ब्लैक-लिस्ट किया गया था? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह रुपया वसूल हुआ या नहीं?

MR. SPEAKER: How can the Steel Minister answer about income-tax?

SHRI SHEO NARAIN: They said that the firm was going to be suspended. Why was it suspended. What happened to the income-tax arrears?

MR. SPEAKER: I know that the hon. Member's question is very important, but the Steel Minister cannot answer it. That is the only difficulty. In regard to income-tax how can the question be answered by the Steel Minister?

SHRI SHEO NARAIN: This relates to Aminchand Pyarelal.

MR. SPEAKER: Everything pertaining to Aminchand Pyarelal cannot be answered by one Minister.

SHRI S. M. BANERJEE: He wants to know whether this was one of the causes for blacklisting. He should answer this.

MR. SPEAKER: If the hon. Minister can answer it, I have no objection.

SHRI S. M. BANERJEE: He should answer the question.

श्री एस० एम० जोशी: वह पूछ रहे हैं कि क्या यह भी एक कारण था या नहीं?

श्री प्र० चं० सेठी: ब्लैक-लिस्ट तो उन का हुआ ही नहीं, उन के साथ बैनिंग हुआ था.... **(व्यवधान)**...

श्री कंवर लाल गुप्त: इस फर्म के खिलाफ़ सी० बी० आई० ने कितने बार एन्क्वायरी की और किन किन एलीगेशन्ज़ पर की? सी.बी.आई. की फाइण्डिंग्ज़ क्या हैं तथा उन फाइण्डिंग्ज़ के आधार पर सरकार ने उन पर क्रिमनल केस क्यों नहीं चलाया?

SHRI P. C. SETHI: I could not say about the all Government Departments and all the CBI reports and on all the subjects. This is a bigger question which would involve perhaps other Ministries also.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: What are the main findings of the CBI? Tell him to tell us the main findings of the CBI.

SHRI P. C. SETHI: In what respect and in what connection? Unless the particular reference is given, how can I say?

SHRI RANGA: Arising out of his answer concerning the CBI reports in regard to this infamous firm of Aminchand Pyarelals, would the hon. Minister, since he does not have the information now, look into all those records and be good enough to place those recommendations on the Table of the House as soon as possible, if not immediately during this session at least by the time we come back for the next session?

Shri S. M. Banerjee has already referred to it, and, therefore, I need not mention names of those great dignitaries. Would the hon. Minister be good enough to say specifically one thing? In regard to these allegations that have been made, this is not the first time that these allegations have been made. This is not the first time that these names have been mentioned in this House; several times in the past they have been mentioned, and the Ministers concerned also had something to say in this House.

Would the hon. Minister be good ehough to say whether that particular CBI report was placed before the Sarkar Committee and whether also, after the CBI concludes its report on the query made by the Reserve Bank of India, that report would be placed before that commission and whether both these reports or their summaries would be placed on the Table of the House?

SHRI P. C. SETHI: I have already stated that with regard to the foreign exchange infringement, the matter is being investigated by the CBI. With regard to the imports that this party has done in excess of what they were allowed to do, about two or three cases relating to these imports are under inquiry by the CBI.

As regards the other question about the other subjects on which the CBI has inquired into the working of this firm, I shall certainly collect the information and place it on the Table of the House.

श्री रवि राय: इस रिपोर्ट में दो डिगनेटरीज़ के नाम हैं या नहीं?

SHRI P. C. SETHI: Which report?

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

†696. **श्री ओंकार सिंह**:
श्री जगन्नाथराव जोशी:
श्री राम गोपाल शालवाले:

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में हाल ही में केवल मध्य प्रदेश के ही इंजीनियरों की नियुक्ति की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण भूमिगत तारों के मामले में एक लाख रुपये तक की हानी हुई है और अपेक्षित दस्तावेजों के समय पर बम्बई पत्तन में न पहुंचने के कारण हानि के रूप में एक लाख रुपये की हानि हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसी लापरवाही के कारण 30,000 रुपये के मूल्य की 4,700 लिटर वार्निश भी नष्ट हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी पाये गये अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फ़खरुद्दीन अलीअहमद): (क) से (घ): एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि०, भोपाल द्वारा पिछले 10 वर्षों में लगभग 500 स्नातक अप्रैंटिस इंजीनियरों की अखिल भारत के आधार पर भर्ती की गई थी। तथापि, हाल ही में केवल मध्य प्रदेश के आवेदकों में से तथा कम्पनी के निम्न पदों से पदोन्नति के द्वारा 31 इंजीनियरों के एक दल का चयन किया गया था। ऐसा इसलिए हुआ कि केवल इसी राज्य से कई सौ अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों ने आवेदन दिये थे और आवश्यकता कम व्यक्तियों की होने के कारण व्यवस्थापकों ने इन्हीं उम्मीदवारों तक चयन सीमित रखा। व्यवस्थापकों के इस निर्णय का सरकार ने अनुमोदन नहीं किया और व्यवस्थापकों ने अब इसकी पुष्टि कर दी है कि भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जायगी।

(ख) दिसम्बर, 1960 में कम्पनी ने 594,798 रु० के मूल्य के ज़मीन के नीचे बिछाये जाने वाले केबलों के लिये आर्डर दिया था। अगस्त, 1961 में 55,088 रु० के मूल्य के केबलों की पूर्ति हो जाने के बाद शेष के लिये आर्डर रद्द कर दिया गया था क्योंकि जो माल दिया गया वह सन्तोषजनक नहीं समझा गया और 648.600 रु० की लागत के